भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-145

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

स्कूलों में डिजिटल शिक्षा सेवा

†145. श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा सेवाओं के उपयोग को बढाने के लिए कोई योजना/परियोजना/पहल शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजना/परियोजना/पहल के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा सेवाओं हेतु आवश्यक अवसंरचना सहायता हेतु मान्यता प्रदान की गई है;
(घ) क्या सरकार ने विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए कोई संवर्धन/जागरूकता अभियान चलाया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयंत चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुसार, प्रौद्योगिकी पहलों का मुख्य कार्य शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार करना, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना, शिक्षक तैयारी और व्यावसायिक विकास में सहायता करना, दिव्यांगों तक शैक्षिक पहुंच को बढ़ानाऔर प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन आदि से संबंधित प्रक्रियाओं सहित शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करना होगा (एनईपी 2020, प्रौद्योगिकी उपयोग और एकीकरण)।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल चल रही है जोशिक्षा तक मल्टी-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है । इससे देश भर में लगभग 25 करोड़ स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे।

इस पहल के प्रमुख घटक हैं:

- दीक्षा - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा (**एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म**)।
- डीटीएच टीवी चैनल - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चैनल आवंटित किए गए हैं और ये कार्यात्मक हैं। आंध्र प्रदेश को 5 डीटीएच चैनल आवंटित किए गए हैं।
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।
- दृष्टि बाधितों एवं श्रवण बाधितों के लिए डिजिटलरूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेजी) और सांकेतिक भाषा पर विशेष ई-सामग्री विकसित की गई है। यह एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक विचार कौशल को बढ़ावा देने के लिए, दीक्षाप्लेटफॉर्म पर वर्चुअल प्रयोगशालाओं का एक वर्टिकल भी बनाया गया है। कक्षा 6 से 12 तक के विज्ञान और गणित विषयों के लिए 280 वर्चुअल प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देश भर के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से वर्चुअल प्रयोगशालाओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा-कक्ष स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, आईसीटी घटक में कक्षा VI से XII तक के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जो बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन है। स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा-कक्ष स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान उपलब्ध हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान इस प्रकार की योजना/परियोजना/पहल के अंतर्गत शामिल स्कूलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईसीटी प्रयोगशाला अनुमोदन (2020-21 से 2024-25 तक)	स्मार्ट क्लासरूम अनुमोदन (2020-21 से 2024-25 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28	0
आंध्र प्रदेश	2687	5190
अरुणाचल प्रदेश	291	243
असम	3132	6416
बिहार	0	4846
चंडीगढ़	35	186
छत्तीसगढ़	1734	10318
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	98	190
दिल्ली	7	1119
गोवा	3	24
गुजरात	728	7078
हरियाणा	620	3520
हिमाचल प्रदेश	995	2248
जम्मू और कश्मीर	1512	3338
झारखंड	3859	1270
कर्नाटक	1123	1868
केरल	0	509
लद्दाख	119	123
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	1801	7934
महाराष्ट्र	637	3501
मणिपुर	272	544
मेघालय	267	25
मिजोरम	651	238
नागालैंड	0	690
ओडिशा	302	7336
पुडुचेरी	16	145
पंजाब	1881	3885

राजस्थान	2988	12627
सिक्किम	99	301
तमिलनाडु	9115	7044
तेलंगाना	1086	3982
त्रिपुरा	773	886
उत्तर प्रदेश	5565	26746
उत्तराखंड	240	2511
पश्चिम बंगाल	1361	0
कुल	44025	126881

स्रोत:प्रबंध

डिजिटल पहलों को विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा विभिन्न प्रिंट, सोशल मीडिया गतिविधियों, तथा जी-20 तृतीय शिक्षा कार्य समूह बैठक, फ्यूचर ऑफ वर्क प्रदर्शनी, टेक4ईडी एक्सपो और सम्मेलन 2023, जी-20 शिक्षा कार्य समूह बैठक जिसमें "विशेष रूप से मिश्रित अधिगम के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना" पर चर्चा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम-एनईपी की तृतीय वर्षगांठ, प्रथम टेक्नो मेला-2023, सीएलएपी (निरंतर शिक्षण पहुंच परियोजना) मोबाइल वाहन के उपयोग पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिल्ड्रन्स पार्क में बाल मेला, 69वां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) अधिवेशन, 50वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी, भारत पर्व-2024, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली, शिक्षा ज्ञान आदान-प्रदान पर भारत शिखर सम्मेलन जैसे मंचों में भागीदारी जैसी केंद्रित आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न डिजिटल पहलों हेतु आउटरीच गतिविधियाँ शुरू करने की सलाह दी जाती है।

****